19 फरबरी 2017

अमेरिका की राष्ट्रीय रक्षा नीति

डॉ. स्तुति बनर्जी*

दिसंबर में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति/रणनीति (एनएसएस) जारी करने के बाद ट्रंप प्रशासन ने यूएस कांग्रेस के सामने राष्ट्रीय डिफेंस नीति/रणनीति (एनडीएस) पेश की। ट्रंप प्रशासन ने साथ ही इसका संक्षिप्त ब्योरा 19 जनवरी 2018 को जारी किया। इसके साथ ही 2 फरवरी 2018 को अपनी परमाणु नीति की समीक्षा भी जारी की। अमेरिका की ओर से जारी ये दो दस्तावेज उसकी मौजूदा तथा भविष्य की रक्षा नीति की झलक दिखाने वाले हैं।

राष्ट्रीय रक्षा रणनीति

'शार्पिंग द अमेरिकन मिलिट्रीज कंपिटिटिव एज' शीर्षक से एनएसएस डॉक्यूमेंट में शामिल की गई नीतियों को एनडीएस द्वारा आगे बढ़ाने की बात कही गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री जेम्स मैटिस ने कहा कि- "ये रणनीति हमारी सुरक्षा से जुड़े वातावरण की एक स्पष्ट तस्वीर है। इसमें दुनिया में अमेरिका के स्थान पर गहरी नजर रखी गई है।" ये दस्तावेज अमेरिका के सामने पैदा उन चुनौतियों की तस्दीक करता है, जो जटिल वैश्विक सुरक्षा वातावरण के कारण पैदा हुआ है तथा जो स्वतंत्र और खुली अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए अपरोक्ष चुनौती के रूप में सामने आया है।

इसमें कहा गया है कि देशों के बीच सामरिक प्रतिस्पर्धा, न कि आतंकवाद, अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से इस वक्त प्राथमिक चिंता है। अमेरिका की समृद्धि तथा सुरक्षा के लिए कुछ क्षेत्रों से पैदा लंबी अवधि की सामरिक प्रतिस्पर्धा देश के सामने पैदा चुनौतियों के केंद्र में है। अब ये साफ हो चुका है कि चीन तथा रूस दुनिया को एक ऐसा आकार देना चाहते हैं, जिसमें उनकी सत्तावादी और अपनी मर्जी चलाने की सोच सफल हो। वो दूसरे देशों के आर्थिक, राजनयिक तथा

सुरक्षा से जुड़े फैसलों के ऊपर वीटो लगाने की अपनी अथॉरिटी प्राप्त कर रहे हैं। दस्तावेज में ये बात साफ किया गया है कि चीन अपने सैन्य आधुनिकीकरण तथा 'हिंसक' आर्थिक नीतियों के बूते इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को अपने हक में बदलना चाहता है। अमेरिकी नेशनल डिफेंस स्ट्रैटजी (एनडीएस) के घोषित उद्देश्यों में अपनी सैन्य ताकत का आधुनिकीकरण करते हुए दूसरे देशों के प्रति संयत तथा पारदर्शी रहने का दावा भी किया गया है।

रूस की चर्चा करते हुए एनडीएस में कहा गया है कि ये पूर्व सुपरपावर दूसरे देशों के साथ अपने राजनीतिक, आर्थिक तथा राजनयिक सम्बंधों में अपनी वीटो वाली स्थिति रखना चाहता है। रूस ऐसा करते हुए नेटो को बर्बाद कर रहा है। डॉक्यूमेंट में ये भी कहा गया है कि रूस, यूरोप तथा मिडिल ईस्ट में सुरक्षा और आर्थिक ढांचे को बदलना चाहता है। और ये बदलाव वो अपने हक में करना चाहता है।

चीन तथा रूस से मिल रही चुनौतियों के अलावा एनडीएस में ईरान और उत्तरी कोरिया का जिक्र भी प्राथमिकता से किया गया है। इन्हें दुष्ट राष्ट्र की संज्ञा देते हुए दस्तावेज में लिखा गया है कि ये दोनों देश परमाणु हथियारों के पीछे भाग रहे हैं तथा आतंकवाद को प्रायोजित कर अपने-अपने क्षेत्रों के संतुलन और सुरक्षा को नष्ट कर रहे हैं। ये भी कहा गया है कि आतंकवादियों की जन संहार वाले हथियारों तक पहुंच विश्व के सामने बड़ी चुनौती है।

डॉक्यूमेंट में एक ऐसी भरोसेमंद अमेरिकी सेना तैयार करने की बात कही गई है जो बहुआयामी हो तथा जिसका आकलन करना सामने वाले के लिए संभव न हो। इस दिशा में एक समग्र दृष्टिकोण की बात भी कही गई है, जिसमें सरकार के सभी विभागों की भागीदारी हो। साथ ही अहम सैन्य क्षेत्रों में व्यापक आधुनिकीकरण की बात भी कही गई है। न्यूक्लियर तैयारियों की चर्चा करते हुए मिसाइल डिफेंस तकनीक पर जोर दिया गया है तथा उत्तर कोरियाई चुनौतियों के मद्देनजर स्पेस तथा साइबर स्पेस में भी निवेश की बात कही गई है। मारक सैन्य ताकत तैयार करने पर जोर देते हुए दस्तावेज में लाभदायक सहयोग की बात भी कही गई है। कहा गया है कि ऐसा करने से अमेरिका टिकाऊ सामरिक बढ़त प्राप्त कर सकेगा।

राष्ट्रपति की सोच की चर्चा करते हुए दस्तावेज में कहा गया है कि- "हमारा गठजोड़ स्वेच्छा से तथा सबकी जिम्मेदारियों पर आधारित है। हालांकि हम अमेरिकी मूल्यों तथा लोकतंत्र में अपने विश्वास पर खड़े होंगे, परन्तु अपने तौर-तरीकों को दूसरों पर थोपने का प्रयास नहीं करेंगे।" नेटो को लेकर सदस्य देशों से कहा गया है कि वो अपनी सेना के आधुनिकीकरण तथा उनपर खर्च बढ़ाकर अपने वादे तथा जिम्मेदारियां पूरा करे।

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की चर्चा करते हुए कहा गया है कि ये आवश्यक है कि ये क्षेत्र स्वतंत्र तथा साफ-सुथरा रहे जिससे सबकी सुरक्षा एवं समृद्धि की आकांक्षा पूरी हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति को अमेरिकी लक्ष्य बताते हुए कहा गया है कि - "क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण देशों के बीच बेहतर द्विपक्षीय सम्बंधों तथा बहुआयामी सुरक्षा सहयोग से एक स्वतंत्र एवं पारदर्शी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था विकसित करने की कोशिश की जाएगी।" दस्तावेज में ऐसे वर्तमान सम्बंधों तथा प्रयासों को समर्थन देने की बात भी कही गई है। साथ ही अफ्रीका, दुनिया के पश्चिमी हिस्से तथा मिडिल ईस्ट में नए सम्बंध विकसित करने की बात कही गई है।

सिस्टम की परेशानियों की बात करते हुए दस्तावेज में बजटीय अनुशासन तथा बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। कहा गया है कि आधुनिक तकनीक को विकसित करना न सिर्फ अमेरिका के हक में होगा, बल्कि आवश्यक ये भी है कि हम इस सोच को प्रभावशाली तरीके से लागू करने के लिए इसे अपने सिस्टम का अंग बना लें।
डिफेंस रणनीति की आवश्यकताओं पर बल देते हुए कहा गया है कि इसका उद्देश्य दुनिया में अमेरिकी प्रभाव को बढ़ाना, दूसरे देशों से सहयोग को मजबूत करना तथा अपने देशवासियों को सुरक्षा देना है।

परमाणु मुद्रा समीक्षा

परमाणु मुद्रा समीक्षा या न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू (एनपीआर) 2018 जारी करते हुए राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि- "हालांकि पिछले दशक में अमेरिका ने परमाणु हथियारों की संख्या और इनकी भूमिका कम करने का प्रयास किया, परन्तु अन्य परमाणु हथियार संपन्न देशों ने ऐसे हथियारों के जखीरे को न सिर्फ बढ़ाया है, बल्कि उन्होंने अपनी सुरक्षा रणनीति में परमाणु हथियारों की भूमिका को और भी महत्त्वपूर्ण बना लिया है। कई मामलों में तो और परमाणु हथियार विकसित कर दूसरे देशों को धमकाने की भी कोशिश की गई है। अब तक अमेरिकी सरकारों ने अपने परमाणु हथियारों के आवश्यक आधुनिकीकरण, इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा इसके डिलिवरी सिस्टम पर बल नहीं दिया है। एनपीआर 2018 में इन चुनौतियों की चर्चा की गई है। इसमें ये भी चर्चा है कि कैसे परमाणु हथियार अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।"

अमेरिका के विदेश मंत्री जेम्स मैटिस ने कहा है कि- "ये रिव्यू इस मजबूत आधार पर कायम है कि परमाणु हथियार मारक परमाणु हमले की स्थिति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे तथा ये भविष्य में परमाणु हथियारों से संपन्न देशों के बीच परंपरागत और बड़े स्तर के युद्ध रोकेंगे।" एनपीआर में ये भी कहा गया है कि- "एनपीआर 2010 के बाद से अब तक चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं तथा ये परमाणु हथियारों की शक्ल में हैं। अमेरिका आज पहले के मुकाबले बहुत अधिक परमाणु खतरे वाले वातारवरण का सामना कर रहा है। और ऐसा दुनिया भर में बदलती राजनीतिक स्थितियों, परमाणु हथियारों के विकास तथा उनकी तैनाती के कारण हुआ है।"

नेशनल डिफेंस स्ट्रैटजी के दस्तावेज में रूस तथा चीन की चर्चा करते हुए कहा गया है कि ये दोनों देश लगातार अपनी परमाणु क्षमता में विस्तार कर रहे हैं जबकि अमेरिका परमाणु हथियारों की संख्या कम करने में जुटा है। हालांकि इसमें ये भी कहा गया है कि इसके बावजूद अमेरिका इन दोंनों देशों को गलत दृष्टिकोण से नहीं देखता है तथा इनके साथ बेहतर और स्थायी सम्बंधों की आशा रखता है। अमेरिका का प्रयास है कि इन दोनों देशों के साथ न सिर्फ बेहतर समझ बढ़े, बल्कि कोशिश इस बात की भी है कि इनके साथ आपसी सम्बंधों में किसी भी प्रकार की गलतफहमी की आशंका कम रहे। इससे आगे दस्तावेज में उत्तरी कोरिया का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि ये देश गलत इरादे से परमाणु हथियारों तथा मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है, और ऐसा

करते हुए वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नियमों की भी अनदेखी कर रहा है। दस्तावेज में ईरान की चर्चा करते हुए कहा गया है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम में कटौती की बात करता है जबकि सच ये है कि उसे ऐसी तकनीकी क्षमता प्राप्त है, जिससे एक साल के अंदर परमाणु हथियारों का निर्माण किया जा सके। इसमें ये भी कहा गया है कि अमेरिका रासायनिक, जैविक, अंतरिक्ष तथा साइबर से जुड़े खतरों के साथ-साथ आतंकवादी समूहों की चुनौतियों का भी सामना कर रहा है।

एनपीआर में इस बात का भी उल्लेख है कि परमाणु हथियारों के विरुद्ध मुहिम में मजबूत परमाणु रणनीति तथा परमाणु हथियारों की भी आवश्यकता है। सोच ये है कि अमेरिका को किसी भी स्तर पर परमाणु हमले की स्थिति में बचाया जा सके। अमेरिका की सुरक्षा रणनीति में अमेरिकी परमाणु सेना निम्नलिखित भूमिका निभाते हैं :

> परमाणु तथा गैर परमाणु हमलों का निवारण - गैर परमाणु आक्रामकता तथा सीमित परमाणु हथियारों के विस्तार से कोई लाभ नहीं होगा। इन पर किसी भी गलतफहमी को दूर करना यूरोप तथा पूर्वी एशिया में शांति के लिए आवश्यक है। अमेरिका स्वयं के विरुद्ध पैदा परेशानियों से निपटने के लिए उसी के अनुरूप तथा लचीली सोच का पक्षधर है। ऐसा करने के लिए अमेरिका अपनी परमाणु क्षमता में बदलाव, एनसी3 (कमांड, कंट्रोल तथा कम्यूनिकेशन) के आधुनिकीकरण तथा परमाणु और गैर परमाणु मिलिट्री योजना को मजबूत करने के साथ-साथ उन्हें आपस में जोड़ने का काम करेगा।

> गठबंधन तथा सहयोगियों को विश्वास - अमेरिका ने परमाणु हथियारों के निवारण का प्रयास किया है तथा अपनी इस प्रतिबद्धता पर कायम रहेगा। ऐसा करने से अमेरिका के परमाणु अप्रसार के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकेंगे।

> अगर अप्रसार के प्रयत्न विफल रहे, तो इस सूरत में अमेरिकी उपलब्धि – अमेरिका अपनी प्रथम प्रयोग नीति पर कायम है जैसा एनपीआर में कहा गया है कि बिलकुल आवश्यक हो जाने पर ही देश तथा अपने सहयोगियों के व्यापक हित में परमाणु हथियारों का उपयोग करेगा।

> अनिश्चित भविष्य के विरुद्ध क्षमता विकसित करना– एनपीआर के अनुसार रणनीति बनाकर धमकियों तथा जोखिमों को कम किया जा सकता है। अमेरिका को इस बात का विश्वास है कि वो अपनी परमाणु क्षमता को बढ़ाकर अपनी सुरक्षा के मामले में बढ़त की स्थिति में होगा।

दस्तावेज में कहा गया है कि ऊपर बताए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए परमाणु कार्यक्रम के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है और विशेषकर नीतियों में लचीलापन भी आवश्यक है। ये आवश्यक है कि परमाणु अप्रसार क्षमता टिकाऊ हो तथा इस बात में सक्षम भी कि मुश्किल परिस्थितियों में एक साथ कई जोखिमों से निपट सके।

अमेरिका मिसाइल कार्यक्रम के आधुनिकीकरण की दिशा में भी काम कर रहा है। साथ ही अपनी परमाणु क्षमताओं को अग्रणी मोर्चों पर तैनात फाइटर प्लेन के साथ जोड़ रहा है। ये सब बी61 बमबर्षक विमानों की उम्र बढ़ाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत हो रहा है।

एनपीआर में ये भी कहा गया है कि हथियारों के आधुनिकीकरण से भी गैर रणनीतिक परमाणु क्षमता में वृद्धि होगी। इससे अग्रणी मोर्चे पर तैनात होने वाले एयरक्राफ्ट अधिक कारगर बनेंगे, सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल को उन्नत बनाने के साथ-साथ समुद्र से प्रक्षेपित होने वाले क्रूज

मिसाइल (एसएलसीएम्स) विकसित होंगे। इन तात्कालिक परिवर्तनों के साथ-साथ लंबी अवधि में अमेरिका परमाणु हथियारों वाले एसएलसीएम के लिए कार्य करेगा। इससे वर्तमान तकनीक का लाभ खर्च कम करने के रूप में मिलेगा। एसएलसीएम की मदद से अमेरिका के लिए आवश्यक गैर रणनीतिक क्षेत्रीय उपस्थिति बढ़ाने में मदद मिलेगी तथा क्षमताओं का भी विकास होगा। इसके द्वारा अमेरिका, रूस की उस सोच की काट निकालेगा, जिसके अन्तर्गत वो ये मानता है कि सीमित तरीके से परमाणु हथियारों के पहले प्रयोग तथा इसके साथ कम क्षमता के हथियारों को रखकर वो दूसरे देशों की तुलना में बढ़त की स्थिति में है। एनपीआर में आधुनिक परमाणु ढांचे के निर्माण पर भी बल दिया गया है। कहा गया है कि अमेरिका के सामने अब इस बात का कोई विकल्प नहीं रह गया है कि हम अपने हथियारों से जुड़े ढांचे को विकसित न करें, जिनके द्वारा परमाणु हथियारों के पूरे सिस्टम के लिए रणनीतिक साजो-सामान तथा पार्ट्स का विकास हो सके। ऐसा करने से गैर रणनीतिक परमाणु क्षमता का भी विकास होगा। एनपीआर में सेना के तीनों ही क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता बताते हुए हथियारों के उपयोग की अवधि बढ़ाने से जुड़े चुनिंदा कार्यक्रम में भी इसे लागू करने पर जोर दिया गया है।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एनपीआर में कहा गया है कि एनसी3 यानी परमाणु कमांड, कंट्रोल तथा कम्यूनिकेशन को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है जो वर्तमान सामरिक वातावरण के अनुकूल हो, जिसमें अंतरिक्ष, साइबर स्पेस, सीमित मात्रा में परमाणु हथियारों के उपयोग जैसी एक साथ मिल रही चुनौतियों से निपटा जा सके। एनसी3 को कारगर बनाने के लिए अमेरिका अपने सिस्टम को साइबर अटैक तथा स्पेस से जुड़ी चुनौतियों से सुरक्षा के लिए कदम उठाएगा। इसके लिए कमांड तथा संचार से जुड़े तंत्र को मजबूत करने की योजना है।

आतंकवादी तथा चरमपंथी समूहों के कारण अमेरिका के सामने पैदा खतरों को देखते हुए एनपीआर में परमाणु आतंकवाद की भी प्रमुखता से चर्चा की गई है। माना जा रहा है कि परमाणु सामग्री या हथियारों तक आतंकवादियों की पहुंच कभी भी बन सकती है। ऐसे में अमेरिका समेत कई देश परमाणु सामग्रियों की सुरक्षा के लिए नियम बनाने में जुटे हैं। इसके अन्तर्गत प्रयास इस बात का है कि परमाणु सामग्री तथा ठिकानों की सुरक्षा बढ़े और साथ ही परमाणु कचरे को ठिकाने लगाने की भी ऐसी व्यवस्था हो, जिससे कि रेडियोएक्टिव पदार्थों तक आतंकवादी समूहों की पहुंच न बन सके। अमेरिका ऐसे किसी भी देश या चरमपंथी गुटों को जिम्मेदार मानेगा, जो किसी न किसी रूप में आतंकवादियों को परमाणु हथियार प्राप्त करने में मदद करेंगे। इस नीति के अन्तर्गत अमेरिका इन विन्दुओं पर कार्य करेगा:

> परमाणु हथियारों, सामग्री, इससे जुड़ी तकनीक तथा जानकारी का गलत उद्देश्यों के लिए उपयोग से रोकना।

> परमाणु आतंकवाद रोकने के लिए मित्र देशों, गठबंधनों तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग बढ़ाना।

> अत्याधुनिक फोरेंसिक क्षमताओं के द्वारा परमाणु आतंकवाद समर्थक देशों पर लगाम कसना।

> परमाणु आतंकवाद के विरुद्ध अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करना, जिससे अमेरिकियों तथा अमेरिका की घर पर और घर से बाहर रक्षा की जा सके।

> ऐसी तैयारी करना, जिससे किसी परमाणु खतरे की स्थिति में कम से कम नुकसान हो सके।

एनपीआर में कहा गया है कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ परमाणु हथियारों तथा सामग्रियों को उनके स्रोत के स्तर पर ही सुरक्षा देगा। और अमेरिका या उसके सहयोगी देशों पर किसी भी परमाणु हमले का किसी भी हद तक जाकर जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के पास ऐसी फोरेंसिक क्षमता है, जिसके द्वारा ये देश इस बात की जानकारी प्राप्त कर सकता है कि जिस परमाणु हथियार का प्रयोग किया गया है, उसमें किस स्रोत से सामग्री जुटाई गई है।

अमेरिका ने इस बात पर जोर दिया है कि हालांकि देश वर्तमान तथा भविष्य में परमाणु खतरों को देखते हुए अपने परमाणु हथियारों के आधुनिकीकरण पर बल दे रहा है, परन्तु इसके साथ ही परमाणु निरस्त्रीकरण के अपने व्यापक उद्देश्यों के प्रति पूर्व की भांति प्रतिबद्ध है। अमेरिका का लगातार प्रयास रहेगा कि परमाणु हथियारों वाले देशों की संख्या कम हो। अमेरिका का ये भी मानना है कि परमाणु हथियार बनाने लायक सामग्री तथा तकनीक के ट्रांसफर पर रोक के लिए आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट पर भी बल देने की आवश्यकता है।

अमेरिका दूसरे देशों के साथ इस उद्देश्य से कार्य करेगा जिससे कि आतंकवादी समूहों को परमाणु सामग्रियों तथा तकनीक तक पहुंच से रोका जा सके। हालांकि अमेरिका समग्र परमाणु टेस्ट बैन ट्रीटी पर सहमत नहीं है, परन्तु समग्र परमाणु टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन प्रीपरेटरी कमेटी का समर्थन करता रहेगा। साथ ही इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम तथा इंटरनेशनल डेटा सिस्टम का भी पक्षधर होगा। अमेरिका तब तक परमाणु हथियारों के परीक्षण से बचेगा, जब तक ऐसा करना अमेरिकी सुरक्षा के लिए आवश्यक न हो। या फिर अमेरिकी परमाणु ताकत को कारगर बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक न हो जाए। इसके साथ ही अमेरिका तमाम परमाणु ताकत संपन्न देशों से कुछ समय के लिए परमाणु परीक्षण पर रोक की घोषणा की अपील करता है। रूस तथा अमेरिका के बीच हुए नए START की चर्चा करते हुए एनपीआर में कहा गया है कि ये आपसी सहमति फरवरी 2021 तक लागू है और ये संभव है कि इस 5 सालों के लिए 2026 तक बढ़ा दिया जाएगा। हालांकि रूस पर आरोप लगाया गया है कि उसने सामरिक तथा गैर रणनीतिक सैन्य ताकत की कटौती के मामले में अपने कई कदमों से START के पहल की उपेक्षा की है।

उपसंहार

एनडीएस तथा एनपीआर को लेकर जैसा नेशनल सिक्यूरिटी स्ट्रैटजी में कहा गया है कि अमेरिका, रूस तथा चीन की शक्ल में शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का दौर आरम्भ हुआ है। अमेरिकी दस्तावेज में कहा गया है कि रूस अपने आर्थिक तथा राजनयिक प्रभावों का इस्तेमाल कर अपने आसपास के देशों में सुरक्षा से जुड़े वर्तमान समीकरण को बदलना चाहता है। रूस अपनी ताकत का प्रयोग कर जॉर्जिया, यूक्रेन तथा क्रीमिया जैसे देशों की राजनीतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहा है। इसके साथ-साथ रूस अपने न्यूक्लियर हथियारों का अधुनिकीकरण कर अमेरिकी सुरक्षा नीति तथा अमेरिकी सेना के लिए चुनौती बनता जा रहा है।

चीन को लेकर इसी तरह के दृष्टिकोण के साथ अमेरिकी दस्तावेज में कहा गया है कि चीन अपने सैन्य तथा आर्थिक नीतियों का उपयोग कुछ देशों के विरुद्ध अपनी ताकत दिखाने में कर रहा है

तथा इसके पीछे उसके दिमाग में बड़ी लंबी अवधि की योजना है। चीन का प्रयास है कि वो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र से निकट भविष्य में अमेरिका को बाहर कर दे। चीन का इरादा भविष्य में दुनिया में अपनी उपस्थिति और मजबूत करने का है। नेशनल डिफेंस स्ट्रैटजी में इंडो-पैसिफिक अलायंस तथा नेटो से पहले यहां अमेरिकी सहयोग की चर्चा करते हुए कहा गया है कि इसी से पता चलता है कि इस इलाके का अमेरिका के लिए कितना महत्व है। परन्तु देखने की बात ये होगी कि अमेरिका के लिए इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के महत्त्व को समझते हुए नेशनल डिफेंस स्ट्रैटजी से जुड़ी नीतियां जमीनी स्तर पर किस हद तक लागू होती हैं।

अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की ओर से जारी दोनों दस्तावेजों में रखे गए विन्दुओं तथा उसकी भाषा के द्वारा देश के सामने पैदा मुश्किलों से निपटने की बात करते हुए अमेरिकी नागरिकों को देश की सुरक्षा से जुड़े एजेंडे को लेकर सजग और सतर्क करने की कोशिश की गई है। दस्तावेज में उन नीतियों तथा सोच का उल्लेख किया गया है, जिनपर वर्तमान अमेरिकी प्रशासन भविष्य में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चलने वाला है। भविष्य में जिन क्षेत्रों से अमेरिका की सुरक्षा को खतरे की आहट है, उनपर प्रशासन तथा रक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के बीच व्यापक सहमति बनाई गई है।

दोनों ही दस्तावेजों में अमेरिका के लिए दूसरे देशों के साथ सहयोग तथा गठजोड़ की आवश्यकताओं पर बल दिया गया है। साथ ही वर्तमान सहयोग को अधिक मजबूत करने की बात कही गई है। ये भी कहा गया है कि सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में नए सहयोगी तलाशने की भी आवश्यकता है।

अमेरिकी सेना तथा उसके संसाधन पूरी दुनिया में तैनात हैं। अमेरिकी दस्तावेज में देश की परंपरागत तथा परमाणु रक्षा क्षमताओं के आधुनिकीकरण पर बल दिया गया है, जिससे मुश्किल समय में इनका प्रयोग सबसे प्रभावी तरीके से किया जा सके।

अमेरिका अपने मिशन की कोई सुनिश्चित सीमा या तारीख की घोषणा नहीं करेगा, जिससे विरोधियों के लिए उसका मुकाबला करना आसान हो जाए। दोनों ही दस्तावेजों में सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण पर बल देते हुए सेना के लिए अधिक बजट के प्रावधान की बात कही गई है। इन दो दस्तावेजों में कहा गया है कि रक्षा विभाग अपने बजट के उपयोग में पारदर्शी है तथा प्रशासन की ओर से बढ़ाए गए बजट को सही साबित कर रहा है।

राष्ट्रपति ट्रम्प ने कांग्रेस के सामने $639.1 से $574.5 बिलियन बजट का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही ओवरसीज ऑपरेशन के लिए $64.6 बिलियन का प्रावधान अलग से किया गया है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में स्पेस तथा साइबर क्षमताओं के विकास पर भी बल है। इसके लिए तकनीक विकसित करने तथा इसे सिस्टम से जल्द से जल्द जोड़ने की बात कही गई है।

नेशनल सिक्यूरिटी स्ट्रैटजी यानी एनएसएस ने अमेरिका के सामने पैदा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के बारे में स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है। देश इन चुनौतियों का सामना कैसे करेगा इस बात को लेकर एनडीएस और एनपीआर मिलकर अपनी रणनीति पर काम करेंगे।

****

*डॉ. स्तुति बनर्जी, शोध अध्येता, विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली।

डिस्क्लेमर: उपरोक्त विचार शोध अध्येता के निजी विचार हैं तथा परिषद के विचारों को प्रतिबिम्बित नहीं करते।